

THE GURUKULAM SCHOOL

A PHYSICSWALLAH SCHOOL

THE GURUKULAM SCHOOL

YOUR FUTURE,
OUR COMMITMENT

Exciting Opportunity for
Grade XI Students

Prepare for Top Careers
CA, CUET, UPSC
Test Preparation
within the School

Limited Seats
Available!

LEARN | PREPARE | SUCCEED

With

100% Off on Admission Fee

10% Off on Tuition Fee

APPLY NOW

7314851919

Varanasi Daafi, Mughalsarai Bypass NH2

व्रती महिलाओं ने सूर्य को दिया अर्घ्य

चंचल सिंह

डीडीयू नगर। लोक आस्था का महापर्व चैती छठ पर गुरुवार को व्रती महिलाओं ने सरोवर तटों पर पहुंच कर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। इसके पहले गीत गाते हुए महिलाएं सरोवर तटों पर पहुंची। इस दौरान कांच ही कांच के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, मार बो रे सुगवा धनुष से, सुगा जडहें मुरछाएं आदि गीतों से सरोवर तट गुलजार रहे। चार दिवसीय चैती छठ की शुरूआत मंगलवार को नहाय खाए के साथ हुई थी।

व्रतियों ने निराजल व्रत रखकर शाम को घाट की पूजा की और दीपदान किया। इसके बाद घर में बखीर तैयार कर इसका भोग लगाया और जल ग्रहण किया। इसके साथ 36 घंटे के उपवास की शुरुआत की। वहीं बृहस्पतिवार को दिन भर शाम को अस्ताचल गामी सूर्य को अर्घ्य देने की तैयारी की। घरों में गुड़ और आटे का ठेकुआ



आदि तैयार की। वहीं बाजार से विभिन्न प्रकार के फल मंगाए। दोपहर बाद सूप और दउरी में फल, पकवान, पूजन सामग्री आदि सजाए। इसके बाद नए कपड़े पहन कर सरोवर तटों पर पहुंचे। नगर के मालगोदाम पोखरा, मानसरोवर

तालाब, दामोदरदास पोखरा आदि स्थानों पर व्रती परिवार के साथ गीत गाते हुए पहुंचे।

यहां घाट पर कलश स्थापित किया, विधि विधान से पूजा की और कमर भर पानी में पहुंच कर सूर्य के अस्त होने का इंतजार

किया। जैसे ही सूर्य अस्त होने लगे व्रतियों ने दूध और जल से अर्घ्य दिया। उदयाचल सूर्य को अर्घ्य देकर चार दिवसीय व्रत का समापन किया जाएगा। वहीं छठ व्रत के महेनजर सरोवर तटों पर और घरों में छठी मइया के गीत गुंजते रहे।

वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर अलर्ट

डीडीयू नगर। वक्फ संशोधन विधेयक बुधवार को लोकसभा में पेश कर दिया गया। इसे देखते हुए डीडीयू नगर समेत आस पास के इलाकों में पुलिस हाई अलर्ट पर है। दूसरे दिन गुरुवार को कोतवाली पुलिस पूरी तरह अलर्ट रही। बुधवार की सुबह मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में पुलिस ने गश्त किया था। आबादी वाले संवेदनशील इलाकों की निगरानी पुलिस के स्तर से बढ़ाई गई। नगर सहित आस पास के क्षेत्रों में दंगा नियंत्रण कानून लागू कर दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए करीब 50 संवेदनशील स्थानों को चिह्नित किया गया। जहां पुलिस और पीएसी बल को दंगा नियंत्रक उपकरणों से लैस कर तैनात कर दिया गया। मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के कसाब महाल, मुस्लिम महाल, इस्लामपुर, अलीनगर, दुलहीपुर को सबसे अधिक संवेदनशील मानते हुए यहां 16 प्रमुख पॉइंट चिह्नित किए गए हैं। जहां पुलिस बल की



विशेष तैनाती की गई है। पुलिस प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और किसी भी अप्रिय स्थिति को निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। एसपी आदित्य लांहे ने बताया कि जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। बताया कि संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही आम जनता से शांति बनाए रखने की

नामांकन अभियान की सीडीओ ने की समीक्षा चंदौली। जनपद में समस्त खंड शिक्षा अधिकारी व विकास खंड प्रभारी प्रधानाचार्यों सहित अन्य प्रधानाचार्य की बैठक बृहस्पतिवार को मुख्य विकास अधिकारी आर जगत साई की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में हुई।इसमें प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश सिंह यादव की ओर से अभियान को सफल बनाने हेतु विस्तृत कार्य योजना के बारे में चर्चा हुई। विद्यालय स्तर पर शत प्रतिशत नामांकन हेतु अभिप्रेरित किया गया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि महत्वाकांक्षी जनपद होने की कारण नामांकन हेतु विशेष नामांकन अभियान चलाया जाए। इसके लिए विकासखण्ड स्तर पर रणनीति बनाई जाए।जनपद में कक्षा आठ पास कुल 40200 बच्चों को नवीन शिक्षक सत्र 2025-26 में नजदीक के विद्यालय में कक्षा नौ में शत प्रतिशत प्रवेश कर लिया जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाय कि कोई भी बच्चा नामांकन से वंचित न रहे।



राम किशन ने बढ़ाया चंदौली का मान, कुशती में जीता गोल्ड मेडल

चन्दौली। ग्राम गुरेहू निवासी पहलवान राम किशन यादव ने लखनऊ में आयोजित नेशनल कुशती चैंपियनशिप में 97 किलो फ्रीस्टाइल में गोल्ड मेडल जीत जिले का नाम बढ़ाया है। राम किशन का एशिया कुशती में चयन हुआ था। 2013 में कुमाउ रेंजिमेंट में उन्हें नौकरी मिली थी। उन्होंने शौर्य न्यूज इंडिया को खास बातचीत में बताया कि इस जीत का श्रेय मेरे पिता घुरहू यादव, माँ और गुरुओं को जाता है। ये लोग हर समय मेरा मनोबल बढ़ाते रहते हैं। उन्होंने बताया कि कुशती में मैं और आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेरा सपना है कि देश के लिए मेडल जीतूँ। इसके लिए मैं तैयारी भी कर रहा हूँ।

स्कूल चलो अभियान के तहत निकाली रैली नौगढ़। सबको शिक्षा, सबको ज्ञान कार्यक्रम के अन्तर्गत गुरुवार को स्कूल चलो अभियान रैली का आयोजन गुरुवार को न्याय पंचायत संकुल केंद्र नौगढ़ से किया गया। जिसका शुभारंभ थानाध्यक्ष कृपेन्द्र प्रताप सिंह व खण्ड शिक्षा अधिकारी लालमणि राम ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर के किया। वहीं प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक भी वितरित किया गया। थानाध्यक्ष कृपेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि सभी शिक्षकों का नैतिक दायित्व है कि अभिभावकों को प्रेरित कर के सभी बच्चों का स्कूलों में नामांकन अवश्य कराएं। शिक्षा के साथ साथ खेलकूद भी जरूरी है, जिससे बच्चों का समुचित शारीरिक मानसिक व सामाजिक विकास हो सके। स्कूल चलो अभियान को सफल बनाने की अपील करते अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से निर्वहन करने के लिए शिक्षकों से कहा। खण्ड शिक्षा अधिकारी लालमणि राम ने बताया कि शिक्षा को काफी सुलभ बनाए जाने में सरकार निरंतर पहल कर रही है।

सड़क दुर्घटनाओं को रोकें: डीएम

चंदौली। जिलाधिकारी निखिल टी फुडें की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा अभियान की समीक्षा बैठक बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। इस दौरान जिले में सड़क दुर्घटनाओं की वर्तमान स्थिति, सुरक्षा उपायों और भविष्य की कार्ययोजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। डीएम ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं और यातायात नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने सड़क सुरक्षा अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने और जनपद में नो हेलमेट, नो फ्यूल अभियान में तेजी लाने का निर्देश दिया। इस दौरान डीएम ने कहा कि सड़कों के स्पांट्स की पहचान एवं सुधार, सड़क दुर्घटनाओं के हॉटस्पॉट चिह्नित किए जाएं।

इन स्थलों पर आवश्यक सुरक्षा उपाय जैसे स्पीड ब्रेकर, साइन बोर्ड, स्ट्रीट लाइट आदि लगाए जाएं।लोक निर्माण विभाग और अन्य संबंधित विभाग मिलकर



मरम्मत कार्य को प्राथमिकता दें।हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सघन अभियान चलाया जाए। नो-हेलमेट, ओवरस्पीडिंग, नशे की हालत में वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। नो हेलमेट,नो फ्यूल अभियान में तेजी लाई जाए। सार्वजनिक स्थलों और मुख्य चौराहों पर यातायात पुलिस की तैनाती बढ़ाई जाए। सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन, पुलिस, परिवहन विभाग और नागरिकों को मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि

सुरक्षित यातायात व्यवस्था केवल नियमों के पालन से ही संभव है, इसलिए आमजन को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी।

उन्होंने सभी अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे लिए गए निर्देशों का गंभीरता से पालन करें और सड़क सुरक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करें। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी डा. वाई के राय, अधिशासी अभियंता (पीडब्ल्यूडी) राजेश कुमार, आरटीओ सर्वेश गौतम, डीएफओ दिलीप श्रीवास्तव, सीओ सदर, खनन अधिकारी आदि उपस्थित रहे।

संक्षेप समाचार...

राइट कर्मनाशा नहर में बेवजह बहाया जा रहा पानी

इलिया। लतीफशाह बांध से निकली राइट कर्मनाशा नहर से बेवजह पानी बहाया जा रहा है। जबकि इस वक्त फसलों की कटाई हो रही है। ऐसे समय में बेवजह पानी को बहाए जाने से धान की बीज डालने के वक्त सिंचाई का गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। गेहूं की तीसरी सिंचाई के लिए 17 दिन तक नहर को चलाए जाने के बाद 11 मार्च से बंद कर दिया गया था। उस वक्त सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बताया था कि बेन राजवाहा में काम होना है इसलिए नहर को बंद कर दिया गया है। अब वह जुलाई माह में धान की रोपाई के वक्त खुलेगी। बुधवार की रात में ही नहर को मछली मारने के लिए ठेकेदारों से मिलकर खोल दिया गया। नहर खुलने पर किसान विकास मंच के नेता रामअवध सिंह ने अधिशासी अभियंता को फोन करके नहर खोलने का कारण पूछा। लेकिन उन्होंने नहर खुलने के बाबत कोई भी जानकारी 12-12 ओवर के मंच में और जैई को निर्देश देकर तत्काल नहर बंद कराय़ा। किसान नेता ने आरोप लगाया है कि हर वर्ष गर्मी के मौसम में विभागीय अधिकारी व कर्मचारी मछली ठेकेदारों से मिलकर बांध के गेट को खोलकर अनयायास पानी बहाते हैं जिससे आगे बारिश न होने पर धान की नर्सरी के लिए किसानों को भारी जिल्लत झेलनी पड़ती है।

मुगलसराय व चंदौली एकादश के बीच गया खेला मैच चंदौली। कीनाराम क्रिकेट क्लब की ओर से गुरुवार को पॉलिटेक्निक कालेज के मैदान में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें टारगेट स्पोर्टिंग क्लब मुगलसराय और चंदौली एकादश के बीच मैच खेला गया। 12-12 ओवर के मैच में पहले टास जीतकर मुगलसराय की टीम ने 12 ओवर में 115 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में उतरी चंदौली एकादश की टीम 75 रन पर ही सिमट गई।

कोठी घाट में धूमधाम से मनी गुह्य राज निषाद जयंती

नौगढ़। भगवान श्रीरामचंद्र के बाल सखा गुह्य राज निषाद जयन्ती समारोह का आयोजन बुधवार को कोठी घाट पर काफी धूमधाम से मनाया गया। जिसमें कताओं ने गुहारज निषाद के जीवन वरित्र पर सविस्तार प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि सुजीत कुमार उर्फ सुहू सिंह, भागपा मंडल अध्यक्ष भगवानदास अग्रहरि व निषाद पार्टी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हंसलाल निषाद ने संयुक्त रूप से गुह्य राज निषाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। निषाद पार्टी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष हंसलाल निषाद ने कहा कि त्रेतायुग में प्रभु श्रीरामचन्द्र व गुहारज निषाद की मित्रता का अनुसरण कलयुग में भी जारी है। ओद्योग्य के महाराजा दशरथ के निदेश पर प्रभु श्री रामपद को 14 वर्षों के लिए वनवास जाते समय निषादराज ने उनकी मदद किया था।रावण राज की समाप्ति पर प्रभु ने अपने दिए गए वचन का पालन करके सच्ची मित्रता का बोध कराय़ा। युवा नेता ने समाज की एकजुटता पर बल देते हुए राजनीति में भागीदारी व बच्चों को शिक्षित किए जाने की अपील किया। रात्रि में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में बिरहा सम्राट राम जन्म जाबाज के नेतृत्व में गायक अखिलेश भारद्वाज संजना चौधरी जितेन्द्र कुमार आदि ने गीत संगीत के माध्यम से समाज की एकता पर बल दिया।

सकलडीहा में स्कंदमाता की सजी झांकी

सकलडीहा। कस्बा के काली माता मंदिर अन्य विभिन्न देवी मंदिरों पर स्कंदमाता की आकर्षक झांकी सजायी गयी थी। शाम को माता का पट खुलते ही भक्त जयकारा लगाते हुए दर्शन पूजन किया। इस दौरान मंदिर के पुजारी की ओर से मां दुर्गा की आरती पढ़ी गयी। इस मौके पर देवी मंदिरों में दर्शन पूजन करने वालों का तांता लगा रहा। कस्बा के काली माता मंदिर,नागेपुर में दुर्गा मंदिर समेत माता मंदिर सहित अन्य देवी मंदिरों पर सुबह शाम वासंतिक नवरात्र में देवी महिलायें पूजा अर्चना में जुटी हुई हैं। देवी मां को प्रसाद चढ़ाने के लिये सुबह से लोगों की भीड़ लगी रहती है। कस्बा के काली मंदिर पर स्कंद माता की झांकी सजायी गयी थी। इस दौरान मां के जयकारा के साथ लोगों ने दर्शन पूजन किया। मंदिर के पुजारी विनय चौबे ने बताया कि मां के नवरूपों का दर्शन पूजन से सार संकट दूर होते है। घर में खुशहाली होती है। इस मौके पर दिलीप मिश्रा, रामजन्म चौबे, नार्गेन्द्र यादव,सुनील सिंह, हसन सुरेन्द्र यादव, सत्यप्रकाश, अनिल सेठ, प्रधान मंजू वर्मा, व्यापार मंडल अध्यक्ष केके सोनी, अशोक कुमार, प्रधान रीता देवी, राजेश सेठ सहित अन्य मौजूद रहे।

चैत्र नवरात्रि: विधि-विधान से पूजी गई मां कात्यायिनी

डीडीयू नगर। आदि शक्ति के उपसना का पर्व वासंतिक नवरात्र में बृहस्पतिवार को माता के छठें स्वरूप मां कात्यायिनी की पूजा अर्चना की गई। भक्तों ने देवी मंदिरों पर पहुंच कर विधि विधान से मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की। वहीं घरों में पुरोहितों को बुलाकर पूजा कर अभीष्ट की कामना की। मंदिरों पर दिन भर माता के जयकारे गूँजे। वहीं शाम के वक्त महिलाओं ने मंदिरों पर पहुंच कर भजन कीर्तन प्रस्तुत किया। वासंतिक नवरात्र में घरों में कलश स्थापित कर माता का आहवान किया गया है। नवरात्र में बृहस्पतिवार को माता के छठें स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की गई। वहीं घरों दुर्गा ससशती, दुर्गा वालीसा, मां विंध्यवासिनी वालीसा आदि का पाठ किया गया। वहीं नगर के जीटी रोड स्थित प्राचीन काली मंदिर, गलेमा मंदी स्थित माता मंदिर, नई सई स्थित आदि शक्ति मंदिर, बड़ी शीतला माता, रविनगर, काली महाल, शाहकुटी, चतुर्भुजपुर, अलीनगर, आरपीएफ कॉलोनी, गया कॉलोनी सहित अन्य देवी मंदिरों पर सुबह से ही दर्शन पूजन के लिए भक्तों के कतार लगी।

स्कूल चलो अभियान के तहतद निकली रैली

चहनीया। कंपोजिट विद्यालय हदयपुर में स्कूल चलो अभियान के तहत रैली निकाली गई। रैली को प्रधानाध्यापक वीरेंद्र सिंह यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सभी बच्चे कतारबद्ध होकर स्लोगन लिखी तख्तियों को लेकर भ्रमण किया और लोगों को शिक्षा के महत्व के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया। गांव के विभिन्न गलियों में घूमते हुए सबको यह संदेश दिया कि विद्यालय में बच्चों का नामांकन जरूर करवा दे। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक वीरेंद्र यादव ने बताया कि स्कूल चलो अभियान का प्रथम वरण, नामांकन और अभिभावक अभिमुखीकरण 1 से 15 अप्रैल तक संचालित किया जा रहा है। अभियान में विद्यालय के शिक्षक नंद कुमार शर्मा, बृजेश कुमार मिश्रा, लक्ष्मीकांत त्रिपाठी, पूजा सिंह, रूबी सिंह ,ममता रानी गुप्ता, गौतम लाल, उमा चौबे, उमेश, राम भजन राम, सुशीला देवी, विजय राज रवि, रसोईया टाता देवी, पिंकी रानी, सुंदरी, केवल देवी सहित सभी बच्चों ने प्रतिभाग किया।



संपादकीय

लापरवाही या घोटाला ?

एक मशीन, जिसे आप और हम 22,000 रुपये में खरीद सकते हैं, उसके लिए सरकार ने हर महीने 1,844 रुपये किराया चुकाया–वो भी लगातार पाँच साल तक ! अब हिसाब लगाइए: 2,100 मशीनों के लिए चार साल में 18 करोड़ रुपये बहा दिए गए, जबकि इनकी कुल कीमत थी बस 4.5 करोड़ रुपये। यह कोई फिल्मी स्क्रिप्ट या मजाक नहीं है, बल्कि दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का असली कारनामा है। एक ऐसा फैसला, जिसने जनता के खून-पसीने की कमाई को पानी की तरह बहा दिया और पुछने वाला कोई नहीं कि आखिर यह हुआ कैसे? यह कहानी सिर्फ मशीनों की नहीं, बल्कि उस सिस्टम की है, जो हमारे टैक्स के पैसे को लुटाने में माहिर हो चुका है।

बात शुरू होती है फरवरी 2021 से, जब दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार का ढोल पीटते हुए एक बड़ा कदम उठाया। उसने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) से 2,100 इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) मशीनें किराए पर लेने का फैसला किया। हर मशीन का किराया तय हुआ 1,844 रुपये प्रति माह, और यह सौदा पाँच साल के लिए पक्का कर लिया गया। चार साल गुजर चुके हैं, और अब तक सरकार ने इन मशीनों के लिए 18 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च कर डाले हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी ये मशीनें सरकार की नहीं हैं—ये आज भी बीईएल की संपत्ति हैं। अब सोचिए, अगर ये मशीनें खरीदी गई होतीं, तो 4.62 करोड़ रुपये में मामला खत्म हो जाता। लेकिन नहीं, सरकार ने किराए का रास्ता चुना और जनता का पैसा हवा में उड़ा दिया।

अब हिसाब को और करीब से देखें। चार साल में 18 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं, और अगर पाँच साल का अनुबंध पूरा हुआ, तो यह रकम 23.25 करोड़ रुपये तक पहुँच जाएगी। यानी, एक मशीन की कीमत से पाँच गुना ज्यादा उसके किराए में दे दिया जाएगा। अगर सरकार ने थोड़ा दिमाग लगाया होता, तो 4.5 करोड़ में ये मशीनें उसकी अपनी हो सकती थीं। रखरखाव का खर्च जोड़ लें, तब भी यह किराए की राशि से आधे से कम पड़ता। मान लीजिए, हर मशीन पर सालाना 5,000 रुपये रखरखाव में लगते—पाँच साल में 25,000 रुपये प्रति मशीन, यानी कुल 5.25 करोड़। फिर भी, खरीद और रखरखाव मिलाकर 10 करोड़ से कम में काम हो जाता। लेकिन यहाँ तो 23 करोड़ रुपये बहाने का प्लान बना लिया गया। यह क्या है—लापरवाही, नासमझी, या कुछ और?

यह सिर्फ दिल्ली की कहानी नहीं है। देश के कोने-कोने में ऐसे फैसले लिए जाते हैं, जहाँ सरकारी खजाना खाली करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। कभी सड़क बनाने के नाम पर घोटाला, कभी स्कूलों के लिए फर्नीचर खरीदने में हेराफेरी, तो कभी अस्पतालों के उपकरणों के नाम पर लूट। हर बार निशाना वहीं होता है—जनता का पैसा। दिल्ली का यह ईपीओएस मशीन मामला तो बस एक झलक है उस सिस्टम की, जो पारदर्शिता और जवाबदेही से कोसों दूर है। 18 करोड़ रुपये कोई छोटी रकम नहीं—इससे कितने बच्चों की स्कूल मिल सकता था, कितने मरीजों को बेड, या कितने गरीबों को राशन? लेकिन यहाँ तो सब कुछ एक बेतुके अनुबंध में बहा दिया गया।

इस लूट को रोकने का रास्ता क्या है? सबसे पहले तो हर सरकारी खर्च की नकैल कसने के लिए एक स्वतंत्र ऑडिट सिस्टम चाहिए। कोई भी अनुबंध हो, उसकी हर डिटेल की जाँच हो, ताकि जनता का पैसा यूँ न लुटे। दूसरी बात, पारदर्शिता को मजबूरी बनाना होगा। हर सौदे की जानकारी—कितना पैसा, किसे दिया, क्यों दिया—यह सब जनता के सामने होना चाहिए। जब लोग जानेंगे कि उनका टैक्स कहाँ जा रहा है, तो सरकार खुद-ब-खुद जवाबदेह बनेगी। तीसरा, ऐसे फैसलों के पीछे बैठे अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराना होगा। अगर कोई गलत नीति बनाता है, जिससे जनता का नुकसान हो, तो उसे सजा मिले—वरना यह सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। सबसे बड़ी ताकत है जनता की जागरूकता। जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक यह लूट चलती रहेगी। सोशल मीडिया पर आवाज उठाइए, आरटीआई दखिल कीजिए, अपने हक के लिए लड़िए। क्योंकि अगर हम चुप रहे, तो यह खेल कभी नहीं थमेगा।

यह मशीनों का मसला कोई साधारण घोटाला नहीं, बल्कि एक ऐसा थप्पड़ है जो सरकारी तंत्र की नींद उड़ा दे—एक चीखती चेतावनी जो हर खेत को बेनकाब करती है। दूरदर्शिता का सुखा, जवाबदेही का दाँग, और जनता के लिए बेशर्मा बेपरवाही—यह सब इस एक फैसले में ठसाठस भरा है। सोचिए एं, 18 करोड़ रुपये का कोई चिल्ला रहे नहीं! इससे गाँवों में बिजली की लकीरें दौड़ सकती थीं, अंधेरे घरों में उजाला खिल सकता था; शहरों में सूखे नलों से साफ पानी की बौछार फूट सकती थी, प्यासी आँखों को राहत मिल सकती थी। लेकिन हकीकत क्या बनी? यह पैसा एक ऐसे सौदे के बर्तन में डूब गया, जो लूट का पर्याय बन गया—न जनता को कुछ हासिल हुआ, न सिस्टम में कोई सुधार आया, बस हवा में उड़ते वादों का ढेर लगा। अब वक़्त है कि हम सब खड़े हों और गरजें—बस, अब और नहीं। यह पैसा हमारा खून-पसीना है, हर उस शख्स की मेहनत है जो टैक्स के बोझ तले दबता है—इसे यूँ डाकुओं की तरह लूटने देना अब गुनाह है। सवाल खड़े करो, जवाब निचोड़ो, और बदलाव की आग सुलगाओ। क्योंकि अगर हम अभी न जागे, तो यह लूट का नंगा नाच कभी नहीं थमेगा।

- **प्रो आरके जैन**

मुद्दों की चासनी में फंसी जनता

देश में मुद्दों की बढ़िया खेती की जाती है। यह मुनाफे वाली फसल होती है। यही वजह असल है। राजनीति में सच्ची-मुच्ची सरल शांति से नहीं कुर्सी मिलती है। लोकतंत्र के खेत में खूब विवाद, शोर-शावये, लम्पट बयानबाजी, गड़े मुद्दे की आतिशबाजी, मारपीट और गाली-गलौज की उर्वरक बहुत जरूरी तत्व होता है।यह लोकतंत्र के खेत को उपजाऊ बनाता है। आजकल मुद्दे में बादशही की कब खोने से लेकर, गद्दार की रार में कानून अपने हाथ में लेकर तक खूब टीआरपी बटोरती है। इतिहास को अपने-अपने ढंग से गढ़ना है। उनका बहादुर राजा अकेले तलवार को थामे देखा तो पूछ ही लिया, अकेले हवाबाजी करके कोई महान कैसे हो सकता है?यह बोलो, 'हमारे इतिहास में यह होता है' बस बात खत्म।

मुद्दों में खूब लफ्फाजी, चुहलबाजी और संवाद में रूढ़ा रूढ़ी भी होती है। इसमें बेमतलबी मुद्दे का बहुत योगदान रहता है। अक्सर मुद्दों में भगवा वीएस हरा का मैच फिक्स होता है।यह सदाबहार मुद्दा है। सब अपनी ही हनक में रहते हैं। हर मुद्दे के समर्थक है। वह अपने मुद्दों को महान ही समझता है। अधंभक्त मुद्दों में सिर्फ इसलिए खड़ा या पड़ा है कि मुद्दों को वैक्कर दाल -रोटी से ऊपर उठा जा सके। बेमतलब के मुद्दों की नंगी पंमत में बैठ कर खाने में मजा भले न आए लेकिन उसका मतलब सध जाता है। उसकी अंतरात्मा सड़ाध मारती है।

बा मुलाईजा खबरदार होशियार मुद्दे की रोटी ठंडी होने पर तू तू मैं में बंद हो जायेगी। बात बने ना बल्कि इतनी विंगड जाए कि मार-पीट हो। इससे कुर्सी पर लंबे समय तक बैठ सकते हैं। बेकार मुद्दा बाँटने वाले या खिलाते वाले धायत नहीं होते बल्कि मुद्दा का चारा खानेवाली मछली फंसीती है। ये देश में बहुत होता है। लोग मुद्दों की क्रीम पाउडर से तैयार होकर ही जाते हैं कि किस बात पर भिड़ना है। कहाँ झमा करना है? मुद्दों की फसल काटने से पहले पकने तक पैनी निगाह रखते हैं। फसल का असल निरीक्षण करते हैं। अब यह नया मुद्दा ही देख लो ! राजा या बादशाह कौन महान में जहान लट रहा है। बेकार मुद्दा बाँटने वाला भी विनम्रता से किसी को नहीं बोलता। हा, यह बात और है कि क्या लोकतंत्र में टाइटम से मुद्दों को खा रहे है? कई बार जनता अपनी अन्य मौज-मस्ती में इतने बिजी होते हैं कि मुद्दों को खाने का होश ही नहीं रख पाते। इससे मुद्दों की फसल गिरकर खराब हो जाती है। आखिर में कुछ नहीं मिलता है। बेवारे रोते-रोते फौजदारी पर ही उतर आते हैं। अपने पूर्वजों को महान बनाने की बहुत मंच-मंच रहती है। जिससे वे बहुत गिरी हुई हरकत कर जाते हैं। गिरना राजनीति में उत्थान का प्रतीक है। गिरावट से ऊपर उतरता है। गड़ा मुद्दा इतना जबरा होना चाहिए कि सब दो बार सोचने पर मजबूर हो जाएं कि किधर जाया जाए या नहीं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि बेमतलबी मुद्दों से असीमित संभावनाएं और अवसर हैं। लोकतंत्र में कुछ ही कंट्रोल कर पाते हैं। - सुर्यदीप कुशवाहा

रविभूषण

भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना प्रमुख भारतीय उद्योगपति स्वर्गीय साहू शान्ति प्रसाद जैन और उनकी पत्नी स्वर्गीयां श्रीमती रमा जैन ने 18 फरवरी 1944 को की थी। संस्कृत, प्राकृत, पाली और अपभ्रंश की धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र, व्याकरण, ज्योतिष शास्त्र, काव्य शास्त्र से जुड़ी पुस्तकों का प्रकाशन इसका मुख्य लक्ष्य था। ज्ञानपीठ ने दर्शन एवं ज्ञानाधारित पुस्तकों के प्रकाशन के लिए 'मूर्तिदिवी ग्रंथमाला' और रचनात्मक साहित्य के प्रकाशन हेतु 'लोकोदय ग्रंथमाला' के तहत अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित की हैं। इसने 'ज्ञानोदय' नाम से जनवरी 1949 से फरवरी 1970 तक एक पत्रिका प्रकाशित की, जो अब 2003 से 'नया ज्ञानोदय' नाम से प्रकाशित हो रही है। इसने अखिल भारतीय स्तर के दो साहित्यिक पुरस्कार आरंभ किये। 22 मई 1961 को भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक साहू शान्ति प्रसाद जैन की पचासवीं वर्षगांठ पर उनके पारिवारिक सदस्यों के मन में साहित्यिक या सांस्कृतिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योजना के प्रवर्तन का विचार आया, जिसे व्यावहारिक रूप प्रदान करने में श्रीमती रमा जैन की मुख्य भूमिका रही। इस योजना को साकार करने के लिए, इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के साहित्यकारों से विचार-विमर्श किया गया। इस योजना को अंतिम रूप देने के लिए "2 अप्रैल 1962 को दिल्ली में भारतीय ज्ञानपीठ और टाइम्स ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में एक बृहद विचार-गोष्ठी का आयोजन हुआ जिसमें देश की सभी भाषाओं के लगभग 300 मूर्धन्य साहित्यकारों ने भाग लिया।" संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं में से सर्वश्रेष्ठ पुस्तक को दिये जाने वाले ज्ञानपीठ पुरस्कार का आरंभ 1965 में हुआ।18वें पुरस्कार (1982) से यह पुरस्कार लेखक के सम्पूर्ण अवदान पर दिया जाता है। आरंभ में पुरस्कार-राशि 1 लाख रुपये थी, जो अब 11 लाख रुपये हो चुकी है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय भाषाओं में दिया जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुरस्कार है।

ज्ञानपीठ पुरस्कार की 'श्रीमती रमा जैन का मानस पुत्र' भी कहा जाता है। इस पुरस्कार की अपनी एक चयन-प्रक्रिया है। सर्वप्रथम ज्ञानपीठ 'विभिन्न भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों, अस्थापकों, समालोचकों और प्रबुद्ध पाठकों' से, विश्वविद्यालयों, साहित्यिक तथा भाषायी संस्थाओं से भी प्रस्ताव भेजने का अनुरोध करता है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक परामर्श-समिति है, जिसके सदस्य प्रसिद्ध साहित्य-समालोचक और विद्वान होते हैं। यह समिति तीन वर्ष की होती है। इससे प्राप्त प्रस्ताव संबंधित 'भाषा परामर्श समिति' के पास भेजा जाता है। भाषा परामर्श समिति प्राप्त प्रस्ताव के अतिरिक्त अन्य नामों पर भी विचार कर सकती है। सबसे ऊँची और प्रमुख समिति 'प्रवर समिति' (परिषद्) है, जिसके सदस्यों की संख्या कम से कम 7 और अधिकतम 11 होती है। प्रवर समिति के सदस्य प्रसिद्ध और विश्वसनीय होते हैं, जिनका कार्यकाल तीन वर्ष का है, पर वह अधिकतम दो बार और अधिक बढ़ाया जा सकता है। अधिकतम नौ वर्ष का कार्यकाल। प्रवर परिषद् के सदस्य ही पुरस्कार-योग्य कवि-लेखक का निर्णय लेते हैं। नियमानुसार पुरस्कार-प्राप्त भाषा पर अगले तीन वर्ष तक विचार नहीं किया जाता है। मुझे यह पता नहीं है कि पुरस्कार का निर्णय सर्वसम्मति से होता है या बहुमत से? किसी नाम विशेष पर प्रवर परिषद् का कोई सदस्य अपनी असहमति लिखित रूप से दर्ज करता है या नहीं? अब तक जो 59 ज्ञानपीठ पुरस्कार दिये गये हैं, उनमें से प्रवर परिषद् के सभी सदस्य क्या एकमत थे या किसी ने किसी नाम पर कभी आपत्ति या असहमति भी प्रकट की? क्या अभी तक प्रवर-परिषद् के सदस्यों में से किसी ने स्वेच्छा से त्यागपत्र दिया है? किस आधार पर प्रवर-परिषद् के किसी सदस्य को तीन वर्ष बाद एक या दो अंश में अधिक दिया जाता है? पुरस्कार के लिए साहित्यकार के चयन का दायित्व प्रवर परिषद् का है, जिसमें न्यासि-मंडल का कोई सदस्य हस्तक्षेप नहीं करता। "प्रवर परिषद् भाषा परामर्श समिति की संस्तुतियों का तुलनात्मक मूल्यांकन करती है।"

ज्ञानपीठ पुरस्कार अब तक 59 लेखकों को प्राप्त हो चुका है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार (1965) मलयालम के जी. शंकर कुरूप को मिला था और 59वाँ पुरस्कार हिन्दी कवि-उपन्यासकार विनोद कुमार शर्कत को प्राप्त हुआ है। हिन्दी के 12, कन्नड़ के 8, बांग्ला के 6, मलयालम के 6, उर्दू के 5, गुजराती के 4, मराठी के

लेख-विचार

ज्ञानपीठ, रामभद्राचार्य और विनोद कुमार शुक्ल



4, ओड़िया के 4, असमिया के 3, तेलुगू के 3, तमिल के 2, कोंकणी के 2, पंजाबी के 2, संस्कृत के 2, कश्मीरी के 1 और अंग्रेजी के 1, कुल 16 भाषाओं के लेखक इस पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। अभी तक सिन्धी भाषा के लेखक इस पुरस्कार से सम्मानित नहीं हुए हैं। छह बार संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार दो लेखकों को प्राप्त हुए हैं। तीसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार (1967) संयुक्त रूप से उमाशंकर जोशी (गुजराती) और कुप्पाली वेंकटप्पा पुट्टप्पा कुवेम्पु (कन्नड़) को, नौवां ज्ञानपीठ पुरस्कार (1973) कन्नड़ के डॉ. वेंदे और ओड़िया के गोपीनाथ मोहंती को, 35वाँ पुरस्कार निर्मल वर्मा (हिन्दी) और गुरदयाल सिंह (पंजाबी) को, 42वाँ पुरस्कार (2006) कोंकणी के रवीन्द्र केलेकर एवं संस्कृत के सत्यव्रत शास्त्री को, 45वाँ पुरस्कार (2009) हिन्दी के दो कथाकारों - अमरकान्त और श्री लाल शुक्ल को एवं 58वाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार (2023) संस्कृत के रामभद्राचार्य और उर्दू के गुलज़ार को संयुक्त रूप से दिया गया है। हिन्दी में सुमित्रा नन्दन पंत, रामधारी सिंह 'दिनकर', अज्ञेय, महादेवी वर्मा, नरेश मेहता, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण, अमरकान्त, श्रीलाल शुक्ल, केदारनाथ सिंह, कृष्णा सोबती और विनोद कुमार शुक्ल ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त कवि-लेखक हैं।

भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की आलोचना सबसे पहले अमिताभ बच्चन द्वारा शहरयात्र को पुरस्कार दिये जाने के समय की गयी थी। इक्कीसवीं सदी का भारत अपने पूर्व मूल्यों-आदर्शों को त्याग कर एक नयी दिशा में बढ़ने लगा था। अमिताभ बच्चन को 'सदी का महानायक' घोषित किया गया और क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेन्दुलकर को 2014 में 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया। 'भारत रत्न' देश का 'सर्वोच्च नागरिक सम्मान' है, जो विज्ञान, साहित्य, कला, जनसेवा और खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। हिन्दी के किसी कवि-लेखक को आज तक 'भारत रत्न' नहीं दिया गया है। रामभद्राचार्य को 58वाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार दिये जाने की काफी आलोचना हुई थी। नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2015 में उन्हें पद्मविभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। उनके पहले 2006 का 42वाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणी लेखक रवीन्द्र केलेकर के साथ सत्यव्रत शास्त्री को संयुक्त रूप से दिया गया था। सत्यव्रत शास्त्री के नाम पर शायद ही किसी ने आपत्ति की हो। सत्यव्रत शास्त्री और रामभद्राचार्य में अंतर है। रामभद्राचार्य उसी प्रकार साहित्यिक नहीं है, जिस प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी कवि नहीं हैं। रामभद्राचार्य हिन्दू धार्मिक-आध्यात्मिक नेता हैं। उनका दलित और मुस्लिम-विरोध किसी से छुपा नहीं है। बाबरी मस्जिद ध्वंस और राम मंदिर निर्माण में उनकी भूमिका थी। वे घृणा और हिंसा के साथ हैं, जबकि साहित्य का इससे बूर है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और शिवसेना के नेताओं को वे मूर्ख कहते हैं। पंडित राजेंद्र मिश्र और शची देवी मिश्र की वे संतान हैं, जिनका जन्म जौनपुर जिला के शांड़ी खुर्द गांव में 14 जनवरी (मकर संक्रान्ति का दिन) 1950 को हुआ था। चित्रकूट में तुलसीपीठ के संस्थापक रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के संस्थापक और उसके आजीवन कुलपति हैं। वे धर्मचक्रवर्ती, महा महोपाध्याय श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर, जगदुरु, महाकवि, प्रस्थान त्रयी भाष्यकार जैसे उपाधियों से सम्मानित हैं। वे अनेक भाषाओं के ज्ञाता और शताधिक पुस्तकों के लेखक के साथ कथावाचक भी रहे हैं। सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से उन्होंने पी-एच.डी. की है। रामभद्राचार्य की धार्मिक कट्टरता सर्वज्ञात है। अभी बीएचयू के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के संधि विषयक व्याकरण प्रबोध कार्यशाला का उद्घाटन करते

हमारा समाज कहां जा रहा है

पिता को उनकी वृद्धावस्था में भारस्वरूप समझते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपत्ति को हड़पने के पश्चात, उनको वृद्धाश्रम में रहने के लिए विवश कर रहे हैं। जो माता-पिता अपनी संपत्ति को अपनी वृद्धावस्था के लिए संचित करते हैं, उनके कुपुत्र अनैतिकता की हद को पार करते हुए, उनके कट्टरता से सम्मानित हैं। वे अनेक हाथ उठाने और उनकी हत्या करने में भी तनिक संकोच नहीं करते।

भारत के वृद्धाश्रम, ऐसे निरीह, असहाय वृद्धजनों से भरे पड़े हैं और नित नए खुल रहे हैं।

1. भारतीय समाज में विवाह एक ऐसा पवित्र बंधन है जो सात जन्मों तक निभाने का वचन देकर, सात फेरों के पश्चात ईश्वर तथा परिवार के वरिष्ठजनों के आशीर्वाद से पूर्ण होता है। पूर्व में विवाह अधिकांशतया माता-पिता की इच्छा से ही होते थे और जो प्रेम विवाह भी होते थे वे विवाह भी परस्पर विश्वास, प्रेम व समर्पण की नींव पर होते थे। परन्तु आज समाज पूर्णतया दिगभ्रमित होता जा रहा है। आज का प्रेम मात्र एक क्षणभंगुर आकर्षण स्वरूप है, जोकि जितनी जल्दी होता है, उतनी ही जल्दी समाप्त हो जाता है। तत्पश्चात लिए गए निर्णय पछतावा अथवा प्रतिशोध में परिवर्तित हो जाते हैं।

2. माता-पिता अपनी संतान के उच्च भविष्य की कामना करते हुए, स्वयं के अथवा परिपक्व संतान की इच्छा से लिए गए निर्णय को स्वीकार करके विवाह करते हैं। परन्तु कुछ बेटा-बेटी विवाह से पूर्व ही विवाहेतर संबंध स्थापित करने के पश्चात विवाह करते हैं, जिसका संज्ञा विवाह के पश्चात

हुए उन्होंने यह कहा है कि मनुस्मृति में एक अक्षर भी राष्ट्र विरोधी नहीं है। उन्होंने ज्ञानवापी पाने तक संघर्ष जारी रखने की बात कही है और मुगलों के नाम पर रखे गये सभी स्थानों के नाम बदलने को कहा है। महाकुंभ में 30 दिनों तक उन्होंने मनुस्मृति पर प्रवचन दिया था। मायावती को 'बहन' कहना उन्हें पसंद नहीं है। उन्हें साहित्य अकादेमी फेलोशिप से सम्मानित किया जा चुका है। उनके साहित्यिक अवदान पर राधा बल्लभ त्रिपाठी ही प्रकाश डाल सकते हैं, जो इस समय संस्कृत के सर्वाधिक प्रतिष्ठित लेखक और विद्वान हैं। रामभद्राचार्य से वे उग्र में भी बड़े हैं।

एक समय था, जब ज्ञानपीठ पुरस्कार समिति के अध्यक्ष काका कालेलकर, डॉ. सम्पूर्णानन्द, डा. कर्ण सिंह, पी वी नरसिम्हा राव, डॉ. लक्ष्मी मिल सिंधवी और डॉ. नामवर सिंह थे। ज्ञानपीठ ने रामभद्राचार्य को पुरस्कृत कर अपनी गरिमा खोई है। रामभद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार (2023) मिल चुका है। जिसकी चयन समिति की अध्यक्ष ओडिया भाषा की सुप्रसिद्ध लेखिका और 47वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रतिभा राय थीं। इस पुरस्कार समिति के सदस्य थे- माधव कौशिक, दामोदर माउजी, सुरंजन दास, पुरुषोत्तम मिश्रा, प्रफुल्ल शिलेदार, हरीश त्रिवेदी, प्रभा वर्मा, जिनकी प्रगसाद शर्मा, ए कृष्ण राव और ज्ञानपीठ के निदेशक मधुसूदन आनंद। देश में जिस प्रकार धार्मिक कट्टरता और 'हिन्दुत्व' को बढ़ावा दिया गया है, यह प्रश्न पूछना जरूरी है कि रामभद्राचार्य का चयन कैसे हुआ? क्या सभी सदस्य उनके नाम पर सहमत और एकमत थे? क्या उनकी धार्मिक कट्टरता से सब अपरिचित थे? क्या इस नाम का किसी ने विरोध किया या अपनी असहमति दर्ज की? रामभद्राचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार देने से ज्ञानपीठ की जो छवि धूमिल हुई थी, उसे उसने 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार (2024) विनोद कुमार शुक्ल को देकर ठीक की है। भारत की किसी भी संस्था अगर अपने पुराने रूप में नहीं है। सबमें फिसलन और गिरावट जारी है। कुछ अपवादों को छोड़ कर ज्ञानपीठ की अब तक साहित्यिक मू्यों एवं गुणवत्ता में निष्ठा रही है। इस समय ज्ञानपीठ और रामभद्राचार्य पर ही नहीं, एक छोटे हलत्के से ही विनोद कुमार शुक्ल पर भी उनके सामाजिक सरोकारों को लेकर सवाल उठाये जा रहे हैं।

विनोद कुमार शुक्ल हिन्दी के अनूठे-अनोखे कवि-उपन्यासकार हैं। उनकी पहचान कलावादी-रूपवादी कवि-उपन्यासकार के रूप में है। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिये जाने के बाद दो -तीन प्रकार की प्रतिक्रियाएं आयी हैं। पहली प्रतिक्रिया में ज्ञानपीठ की प्रशंसा है कि इस बार उसका निर्णय ठीक रहा और उसने अपनी भूल-गलती सुधारी। एक प्रतिक्रिया यह भी आई कि विनोद कुमार शुक्ल को इसे अस्वीकार करना चाहिए था। दो-चार कवियों-लेखकों ने उनके साहित्यिक सरोकार पर भी सवाल उठाये कि वे जिस छत्तीसगढ़ में, रायपुर में रहते हैं, वहाँ राज्यसत्ता, सरकार और पुलिस की बर्बता पर उन्होंने कभी मुंह नहीं खोला और मुक्तिबोध से जुड़े रहने के बाद भी यह तथ नहीं किया कि वे किस और हैं? विनोद कुमार शुक्ल ने कभी सत्ता का मुखर विरोध न किया हो, पर वे सत्ता, व्यवस्था के साथ कभी नहीं रहे हैं।

एकान्त भाव से लेखन के प्रति समर्पित हिन्दी में ऐसा कोई दूसरा लेखक नहीं है। केवल हिन्दी में ही नहीं, भारतीय साहित्य में भी उनका अवदान मौलिक और अन्यतम है। भारतीय ज्ञानपीठ न तो प्रगतिशील है और न क्रांतिकारी। हिन्दी और भारतीय भाषाओं के सभी कवि-लेखक भी प्रगतिशील और मार्क्सवादी नहीं हैं। विनोद कुमार शुक्ल के प्रशंसक अधिक हैं, आलोचक कम। उनके अवदान पर सुचिंतित और सुविचारित रूप से अब तक कम विचार किया गया है। 'लगभग

शौर्य न्यूज़ इंडिया

7 अप्रैल से 13 अप्रैल, 2025

जयहिन्द' (1971) से लेकर उनका अब तक का सृजन-कर्म लगभग पचपन वर्ष का है, जिसे हम पैंसठ वर्ष का भी कह सकते हैं, जब मुक्तिबोध ने उनकी कविताएं श्रीकान्त वर्मा को 'कृति' के लिए भेजी थीं। विचारणीय बात और गंभीर बात यह है कि लगभग एक ही समिति ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए रामभद्राचार्य और विनोद कुमार शुक्ल के नाम पर भी एकमत होती है।

विनाद कुमार शुक्ल का समय अभी एक साथ अप्रकाशित है। 'लगभग पचपन वर्ष का है, जिसे हम पैंसठ वर्ष का भी कह सकते हैं, जब मुक्तिबोध ने उनकी कविताएं श्रीकान्त वर्मा को 'कृति' के लिए भेजी थीं। विचारणीय बात और गंभीर बात यह है कि लगभग एक ही समिति ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए रामभद्राचार्य और विनोद कुमार शुक्ल के नाम पर भी एकमत होती है। विनाद कुमार शुक्ल का समय अभी एक साथ अप्रकाशित है। 'लगभग पचपन वर्ष का है, जिसे हम पैंसठ वर्ष का भी कह सकते हैं, जब मुक्तिबोध ने उनकी कविताएं श्रीकान्त वर्मा को 'कृति' के लिए भेजी थीं। विचारणीय बात और गंभीर बात यह है कि लगभग एक ही समिति ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए रामभद्राचार्य और विनोद कुमार शुक्ल के नाम पर भी एकमत होती है। विनाद कुमार शुक्ल का समय अभी एक साथ अप्रकाशित है। 'लगभग पचपन वर्ष का है, जिसे हम पैंसठ वर्ष का भी कह सकते हैं, जब मुक्तिबोध ने उनकी कविताएं श्रीकान्त वर्मा को 'कृति' के लिए भेजी थीं। विचारणीय बात और गंभीर बात यह है कि लगभग एक ही समिति ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए रामभद्राचार्य और विनोद कुमार शुक्ल के नाम पर भी एकमत होती है। विनाद कुमार शुक्ल का समय अभी एक साथ अप्रकाशित है। 'लगभग पचपन वर्ष का है, जिसे हम पैंसठ वर्ष का भी कह सकते हैं, जब मुक्तिबोध ने उनकी कविताएं श्रीकान्त वर्मा को 'कृति' के लिए भेजी थीं। विचारणीय बात और गंभीर बात यह है कि लगभग एक ही समिति ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए रामभद्राचार्य और विनोद कुमार शुक्ल के नाम पर भी एकमत होती है। विनाद कुमार शुक्ल का समय अभी एक साथ अप्रकाशित है। 'लगभग पचपन वर्ष का है, जिसे हम पैंसठ वर्ष का भी कह सकते हैं, जब मुक्तिबोध ने उनकी कविताएं श्रीकान्त वर्मा को 'कृति' के लिए भेजी थीं। विचारणीय बात और गंभीर बात यह है कि लगभग एक ही समिति ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए रामभद्राचार्य और विनोद कुमार शुक्ल के नाम पर भी एकमत होती है। विनाद कुमार शुक्ल का समय अभी एक साथ अप्रकाशित है। 'लगभग पचपन वर्ष का है, जिसे हम पैंसठ वर्ष का भी कह सकते हैं, जब मुक्तिबोध ने उनकी कविताएं श्रीकान्त वर्मा को 'कृति' के लिए भेजी थीं। विचारणीय बात और गंभीर बात यह है कि लगभग एक ही समिति ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए रामभद्राचार्य और विनोद कुमार शुक्ल के नाम पर भी एकमत होती है। विनाद कुमार शुक्ल का समय अभी एक साथ अप्रकाशित है। 'लगभग पचपन वर्ष का है, जिसे हम पैंसठ वर्ष का भी कह सकते हैं, जब मुक्तिबोध ने उनकी कविताएं श्रीकान्त वर्मा को 'कृति' के लिए भेजी थीं। विचारणीय बात और गंभीर बात यह है कि लगभग एक ही समिति ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए रामभद्राचार्य और विनोद कुमार शुक्ल के नाम पर भी एकमत होती है। विनाद कुमार शुक्ल का समय अभी एक साथ अप्रकाशित है। 'लगभग पचपन वर्ष का है, जिसे हम पैंसठ वर्ष का भी कह सकते हैं, जब मुक्तिबोध ने उनकी कविताएं श्रीकान्त वर्मा को 'कृति' के लिए भेजी थीं। विचारणीय बात और गंभीर बात यह है कि लगभग एक ही समिति ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए रामभद्राचार्य और विनोद कुमार शुक्ल के नाम पर भी एकमत होती है। विनाद कुमार शुक्ल का समय अभी एक साथ अप्रकाशित है। 'लगभग पचपन वर्ष का है, जिसे हम पैंसठ वर्ष का भी कह सकते हैं, जब मुक्तिबोध ने उनकी कविताएं श्रीकान्त वर्मा को 'कृति' के लिए भेजी थीं। विचारणीय बात और गंभीर बात यह है कि लगभग एक ही समिति ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए रामभद्राचार्य और विनोद कुमार शुक्ल के नाम पर भी एकमत होती है। विनाद कुमार शुक्ल का समय अभी एक साथ अप्रकाशित है। 'लगभग पचपन वर्ष का है, जिसे हम पैंसठ वर्ष का भी कह सकते हैं, जब मुक्तिबोध ने उनकी कविताएं श्रीकान्त वर्मा को 'कृति' के लिए भेजी थीं। विचारणीय बात और गंभीर बात यह है कि लगभग एक ही समिति ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए रामभद्राचार्य और विनोद कुमार शुक्ल के नाम पर भी एकमत होती है। विनाद कुमार शुक्ल का समय अभी एक साथ अप्रकाशित है। 'लगभग पचपन वर्ष का है, जिसे हम पैंसठ वर्ष का भी कह सकते हैं, जब मुक्तिबोध ने उनकी कविताएं श्रीकान्त वर्मा को 'कृति' के लिए भेजी थीं। विचारणीय बात और गंभीर बात यह है कि लगभग एक ही समिति ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए रामभद्राचार्य और विनोद कुमार शुक्ल के नाम पर भी एकमत होती है। विनाद कुमार शुक्ल का समय अभी एक साथ अप्रकाशित है। 'लगभग पचपन वर्ष का है, जिसे हम पैंसठ वर्ष का भी कह सकते हैं, जब मुक्तिबोध ने उनकी कविताएं श्रीकान्त वर्मा को 'कृति' के लिए भेजी थीं। विचारणीय बात और गंभीर बात यह है कि लगभग एक ही समिति ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए रामभद्राचार्य और विनोद कुमार शुक्ल के नाम पर भी एकमत होती है। विनाद कुमार शुक्ल का समय अभी एक साथ अप्रकाशित है। 'लगभग पचपन वर्ष का है, जिसे हम पैंसठ वर्ष का भी कह सकते हैं, जब मुक्तिबोध ने उनकी कविताएं श्रीकान्त वर्मा को 'कृति' के लिए भेजी थीं। विचारणीय बात और गंभीर बात यह है कि लगभग एक ही समिति ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए रामभद्राचार्य और विनोद कुमार शुक्ल के नाम पर भी एकमत होती है। विनाद कुमार शुक्ल का समय अभी एक साथ अप्रकाशित है। 'लगभग पचपन वर्ष का है, जिसे हम पैंसठ वर्ष का भी कह सकते हैं, जब मुक्तिबोध ने उनकी कविताएं श्रीकान्त वर्मा को 'कृति' के लिए भेजी थीं। विचारणीय बात और गंभीर बात यह है कि लगभग एक ही समिति ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए रामभद्राचार्य और विनोद कुमार शुक्ल के नाम पर भी एकमत होती है। विनाद कुमार शुक्ल का समय अभी एक साथ अप्रकाशित है। 'लगभग पचपन वर्ष का है, जिसे हम पैंसठ वर्ष का भी कह सकते हैं, जब मुक्तिबोध ने उनकी कविताएं श्रीकान्त वर्मा को 'कृति' के लिए भेजी थीं। विचारणीय बात और गंभीर बात यह है कि लगभग एक ही समिति ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए रामभद्राचार्य और विनोद कुमार शुक्ल के नाम पर भी एकमत होती है। विनाद कुमार शुक्ल का समय अभी एक साथ अप्रकाशित है। 'लगभग पचपन वर्ष का है, जिसे हम पैंसठ वर्ष का भी कह सकते हैं, जब मुक्तिबोध ने उनकी कविताएं श्रीकान्त वर्मा को 'कृति' के लिए भेजी थीं। विचारणीय बात और गंभीर बात यह है कि लगभग एक ही समिति ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए रामभद्राचार्य और विनोद कुमार शुक्ल के नाम पर भी एकमत होती है। विनाद कुमार शुक्ल का समय अभी एक साथ अप्रकाशित है। 'लगभग पचपन वर्ष का है, जिसे हम पैंसठ वर्ष का भी कह सकते हैं, जब मुक्तिबोध ने उनकी कविताएं श्रीकान्त वर्मा को 'कृति' के लिए भेजी थीं। विचारणीय बात और गंभीर बात यह है कि लगभग एक ही समिति ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए रामभद्राचार्य और विनोद कुमार शुक्ल के नाम पर भी एकमत होती है। विनाद कुमार शुक्ल का समय अभी एक साथ अप्रकाशित है। 'लगभग पचपन वर्ष का है, जिसे हम पैंसठ वर्ष का भी कह सकते हैं, जब मुक्तिबोध ने उनकी कविताएं श्रीकान्त वर्मा को 'कृति' के लिए भेजी थीं। विचारणीय बात और गंभीर बात यह है कि लगभग एक ही समिति ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए रामभद्राचार्य और विनोद कुमार शुक्ल के नाम पर भी एकमत होती है। विनाद कुमार शुक्ल का समय अभी एक साथ अप्रकाशित है। 'लगभग पचपन वर्ष का है, जिसे हम पैंसठ वर्ष का भी कह सकते हैं, जब मुक्तिबोध ने उनकी कविताएं श्रीकान्त वर्मा को 'कृति' के लिए भेजी थीं। विचारणीय बात और गंभीर बात यह है कि लगभग एक ही समिति ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए रामभद्राचार्य और विनोद कुमार शुक्ल के नाम पर भी एकमत होती है। विनाद कुमार शुक्ल का समय अभी एक साथ अप्रकाशित है। 'लगभग पचपन वर्ष का है, जिसे हम पैंसठ वर्ष का भी कह सकते हैं, जब मुक्तिबोध ने उनकी कविताएं श्रीकान्त वर्मा को 'कृति' के लिए भेजी थीं। विचारणीय बात और गंभीर बात यह है कि लगभग एक ही समिति ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए रामभद्राचार्य और विनोद कुमार शुक्ल के नाम पर भी एकमत होती है। विनाद कुमार शुक्ल का समय अभी एक साथ अप्रकाशित है। 'लगभग पचपन वर्ष का है, जिसे हम पैंसठ वर्ष का भी कह सकते हैं, जब मुक्तिबोध ने उनकी कविताएं श्रीकान्त वर्मा को 'कृति' के लिए भेजी थीं। विचारणीय बात और गंभीर बात यह है कि लगभग एक ही समिति ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए रामभद्राचार्य और विनोद कुमार शुक्ल के नाम पर भी एकमत होती है। विनाद कुमार शुक्ल का समय अभी एक साथ अप्रकाशित है। 'लगभग पचपन वर्ष का है, जिसे हम पैंसठ वर्ष का भी कह सकते हैं, जब मुक्तिबोध ने उनकी कविताएं श्रीकान्त वर्मा को 'कृति' के लिए भेजी थीं। विचारणीय बात और गंभीर बात यह है कि लगभग एक ही समिति ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए रामभद्राचार्य और विनोद कुमार शुक्ल के नाम पर भी एकमत होती है। विनाद कुमार शुक्ल का समय अभी एक साथ अप्रकाशित है। 'लगभग पचपन वर्ष का है, जिसे हम पैंसठ वर्ष का भी कह सकते हैं, जब मुक्तिबोध ने उनकी कविताएं श्रीकान्त वर्मा को 'कृति' के लिए भेजी थीं। विचारणीय बात और गंभीर बात यह है कि लगभग एक ही समिति ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए रामभद्राचार्य और विनोद कुमार शुक्ल के नाम पर भी एकमत होती है। विनाद कुमार शुक्ल का समय अभी एक साथ अप्रकाशित है। 'लगभग पचपन वर्ष का है, जिसे हम पैंसठ वर्ष का भी कह सकते हैं, जब मुक्तिबोध ने उनकी कविताएं श्रीकान्त वर्मा को 'कृति' के लिए भेजी थीं। विचारणीय बात और गंभीर बात यह है कि लगभग एक ही समिति ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए रामभद्राचार्य और विन

वक्फ संशोधन बिल, नंबर गेम भाजपा के पक्ष में

भाजपा ने व्हिप जारी नहीं किया, जेपी नड्डा बोले- विपक्ष चर्चा को डिरेल करना चाहता है

नई दिल्ली। वक्फ संशोधन बिल बुधवार को लोकसभा में पास होने के बाद गुरुवार को राज्यसभा में पेश किया गया। इस पर देर शाम तक चर्चा चलती रही। बीजू जनता दल ने वक्फ बिल पर कहा है कि पार्टी ने अपने सांसदों को कोई व्हिप जारी नहीं किया है। सांसद अपनी अंतरआत्मा की सुनें और वक्फ बिल पर फैसला लें। फिलहाल यहां नंबर गेम भाजपा के पक्ष में दिखाई दे रहा है। वहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने वक्फ बिल पर विपक्ष के रुख को लेकर निशाना साधा।

नड्डु ने कहा, हमने कंजिस नेतृत्व वाली पीपुीए सरकार की तुलना में वक्फ बिल को लेकर कहीं ज्यादा गंभीरता दिखाई। यह बिल पार्टी इंस्ट्रुट का नहीं है, यह नेशनल इंस्ट्रुट का विषय है। इसलिए मुदे पर चर्चा करनी चाहिए। विषय को डिरेल नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा- बिल में कहीं राम मंदिर आ



रहा है। कहीं कुंभ मेला दिख रहा है। बिहार का इलेक्शन दिख रहा। कहीं एअर इंडिया बिक गया। कहीं केरला का सिनेमा आ गया। ये सब चर्चा को डिरेल करने की कोशिश है। रिजिजू बोले- बिल में ट्रांसपैरेंसी, अकाउटेबिलिटी, एक्स्प्रेसी केंद्रित बदलाव: अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि व्यापक चर्चा के बाद तैयार किए गए बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया था।

वक्फ को लेकर जेपीसी ने जितना काम किया, उतना काम किसी कमेटी ने नहीं किया। इससे पहले बुधवार देर रात तक चर्चा के बाद इस बिल को लोकसभा से पारित कर दिया गया। रिजिजू ने राज्यसभा में कहा, संशोधित बिल में मुसलमानों के धार्मिक क्रियाकलापों में किसी तरह का हस्तक्षेप कोई गैर मुस्लिम नहीं करेगा। हमने ट्रांसपैरेंसी, अकाउटेबिलिटी, एक्स्प्रेसी पर केंद्रित बदलाव किए

जेडीयू में बगावत की चिंगारी

जेडीयू के सीनियर नेता डॉ मोहम्मद कासिम अंसारी ने लोकसभा में वक्फ बिल का समर्थन करने पर पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। अंसारी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना त्याग पत्र भेज दिया है। उन्होंने अपने त्याग पत्र में लिखा, उन्हें और लाखों करोड़ों भारतीय मुसलमानों को विश्वास था कि नीतीश कुमार विशुद्ध रूप से सेक्युलर विचारधारा के ध्वजवाहक हैं, लेकिन अब यह विश्वास टूट गया है। कासिम अंसारी ने वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर जेडीयू के स्टैंड की आलोचना की है और कहा है कि इससे उन्हें और लाखों करोड़ों समर्पित भारतीय मुसलमानों एवं कार्यकर्ताओं को गहरा आघात लगा है। उन्होंने यह भी कहा है कि लोकसभा में ललन सिंह ने जिस तेवर और अंदाज से अपना वक्तव्य दिया और इस बिल का समर्थन किया, उससे वे काफी मर्माहत हुए हैं।

हैं। हम किसी की धार्मिक भावना को चोट पहुंचाने के लिए नहीं हैं। गरीब मुसलमानों की न्याय मिले, हमारा यही उद्देश्य है। इससे पहले लोकसभा में बुधवार को 12 घंटे की चर्चा के बाद वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। रात 2 बजे हुई

वोटिंग में 520 सांसदों ने भाग लिया। 288 ने पक्ष में और 232 ने विपक्ष में वोट डाले। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे उम्मीद (यूनीफाइड वक्फ मैनेजमेंट इम्प्रावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट) नाम दिया है।



कार्रवाई: लॉरेंस गैंग के पांच सदस्य गिरफ्तार

मुंबई। मुंबई क्राइम ब्रांच ने अंधेरी इलाके से लॉरेंस गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 7 पिस्तौल और 21 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। पुलिस ने यह जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें संदेह है कि गैंग के निशाने पर कोई सेलिब्रिटी था। क्राइम ब्रांच के अधिकारी ने बताया कि विशेष सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने लॉरेंस गैंग के सदस्यों को शनिवार को हिरासत में लिया। उनके हथियार ले जाने के पीछे के मकसद की जांच की जा रही है। गिरफ्तार लोगों की पहचान विकास ठाकुर उर्फ विक्की, सुमित कुमार दिलावर, श्रेयस यादव, देवेन्द्र सक्सेना और विवेक गुप्ता के रूप में की गई है। ये सभी राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। सुमित कुमार और विकास हिस्ट्रीशीट हैं।

जहरीली गैस ने ली आठ लोगों की जान



कोहराम

कुएं की सफाई करने उतरे थे सभी, मध्यप्रदेश के खंडवा जिले की घटना तलाश शुरू की गई। सात लोगों के शव निकाल लिए गए हैं, आठवें की तलाश के लिए काफी मशक्कत करना पड़ी। सवा आठ बजे आठवें शव को भी निकाल लिया गया। कलेक्टर त्रश्रभ गुप्ता ने बताया कि शाम करीब 4 बजे घटना की सूचना मिली थी। जहरीली गैस के चलते यह हादसा हुआ है।

तलाश शुरू की गई। सात लोगों के शव निकाल लिए गए हैं, आठवें की तलाश के लिए काफी मशक्कत करना पड़ी। सवा आठ बजे आठवें शव को भी निकाल लिया गया। कलेक्टर त्रश्रभ गुप्ता ने बताया कि शाम करीब 4 बजे घटना की सूचना मिली थी। जहरीली गैस के चलते यह हादसा हुआ है।

न्यायाधीश सार्वजनिक करेंगे अपनी संपत्ति

सुप्रीम कोर्ट के 30 वरिष्ठ जज अपनी संपत्ति वेबसाइट पर करेंगे अपलोड

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करने पर सहमति जताई है। शीर्ष अदालत में हुई न्यायाधीशों की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना सहित 30 न्यायाधीशों ने अपनी संपत्तियों को न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करके सार्वजनिक रूप से प्रकट करने पर सहमति व्यक्त की।

सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट के मुताबिक एक अप्रैल को हुई बैठक में जजों ने संकल्प लिया कि न्यायाधीश जब भी पदभार ग्रहण करेंगे या कोई अहम जिम्मेदारी लेंगे तो उनके मुख्य न्यायाधीश के सामने अपनी संपत्ति की घोषणा करनी होगी। अब तक 1997 के एक प्रस्ताव के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को अपनी संपत्ति की घोषणा मुख्य न्यायाधीश के समक्ष



करनी होती थी। 2009 के एक निर्णय में न्यायालय की वेबसाइट पर संपत्ति घोषणा के स्वेच्छिक प्रकाशन की अनुमति दी गई थी, लेकिन सभी न्यायाधीशों ने ऐसा करने का विकल्प नहीं चुना। अब सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सामूहिक रूप से संपत्ति के खुलासे को सार्वजनिक करने पर सहमति जताई। जिन न्यायाधीशों ने अपनी संपत्ति की घोषणा कर दी है, उनमें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति भूपेन्द्र रामकृष्ण गर्वई, न्यायमूर्ति बीवी नारगला, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी शामिल हैं। घोषणाओं का पूरा सेट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। सुप्रीम

देरी का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित

उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस में शामिल हुए बीआरएफ के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिकाओं पर निर्णय लेने में तेलंगाना विस अध्यक्ष द्वारा कथित देरी का मुद्दा उठाने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति बीआर गर्वई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। एक याचिका में तीन विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली याचिकाओं से संबंधित तेलंगाना उच्च न्यायालय के नवंबर 2024 के आदेश को चुनौती दी गई है। जबकि दूसरी याचिका दलबदल करने वाले शेष सात विधायकों से संबंधित है। पिछले साल नवंबर में उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष को तीनों विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर उचित समय के भीतर फैसला करना चाहिए।

कोर्ट ने यह कदम जस्टिस यशवंत वर्मा मामले के बाद उठाया है। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास पर आग लगने की घटना के बाद कथित तौर पर नकदी की जली हुई

गड्डियां मिली थीं। विवाद के बाद उनका तबादला इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कर दिया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उनका तबादला नकदी मिलने के विवाद से संबंधित नहीं था।

घरेलू टीमों के अनुसार बनाई जानी चाहिए पिच

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में जहां कई टीमों ने पिच को लेकर सवाल उठाये हैं। वहीं पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा का मानना है कि घरेलू टीमों को अपने अनुसार अपना खोज लेंगे। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुंभ 2025 ने देश-प्रदेश को बहुत कुछ दिया। इतना बड़ा आयोजन सतानत धर्मावलंबी और राम भक्त ही कर सकते हैं। जिनके मन में राष्ट्र के प्रति निष्ठा नहीं है, वे ही इतना बड़ा आयोजन नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयागराज अब सामान्य रूप से इलाहाबाद नहीं रहा। अब यह प्रयागराज हो गया है। प्रयागराज का मतलब महामिलन स्थल। जो लोग प्रयागराज की पहचान को छिपाते थे, वे नहीं चाहते थे कि इस पौराणिक नगर को एक पहचान मिले क्योंकि उनके लिए उनका वोटबैंक महत्वपूर्ण था।



प्रदर्शन के लिए सबसे अहम कारक है, यहां तक कि भीड़ के समर्थन से भी ज्यादा। उनका मानना है कि अगर पिच की स्थिति आपके खिलाफ है, तो टीम की पूरी खेल योजना पर पानी फिर सकता है। उन्होंने कहा, सबसे जरूर बात यह है कि वे किस पिच पर खेलने जा रहे हैं। ऐसे में दर्शकों की भीड़ मायने नहीं रखती। साथ ही कहा कि अगर आप पिच को हटा देते हैं, तो मुझे लगता है कि पूरी योजना खराब हो जाएगी।

‘यह वक्फ बोर्ड है या भू-माफिया बोर्ड’ मुख्यमंत्री योगी बोले, ऐतिहासिक स्थलों पर मनमाना दावा बर्दाश्त नहीं होगा



खदेड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि निषाद राज से जुड़ी पवित्र भूमि समेत कई जगहों पर वक्फ के नाम पर अतिक्रमण किया गया। लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। उनकी आपत्तियों के बावजूद भव्य और दिव्य कुंभ मेले का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने वक्फ बोर्ड की कथित अनियमितताओं के खिलाफ विधायी कार्रवाई करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी सलाहना की। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के आभारी हैं कि उन्होंने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगाई है। इस मुद्दे को हल करने वाला एक महत्वपूर्ण विधेयक पहले ही लोकसभा में पारित हो चुका है और अब इसे राज्यसभा में भी पारित किया जाएगा। गौरतलब है कि वक्फ (संशोधन) विधेयक बुधवार को लोकसभा में पारित हो गया और वृहत्संविदा को राज्यसभा में प्रस्तुत होने के बाद उस पर बहस जारी है।

प्रयागराज। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड पर वृहत्संविदा को सीधा हमला करते हुए इस पर भूमि अतिक्रमण करने का आरोप लगाया और इस बात पर जोर दिया कि सार्वजनिक और ऐतिहासिक स्थलों पर इसका मनमाना दावा ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

यहां श्रृंगवेरपुर की सभा में उन्होंने कहा कि आप यहां निषादराज की पौराणिक भूमि पर कब्जा देख रहे हैं ना। शहर में जगह-जगह वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए हैं। यहां तक की कुंभ के समय भी बयान दिए गए कि कुंभ की भूमि भी वक्फ की है। हमने पूछा था-क्या वक्फ बोर्ड भू-माफिया बन गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनकी सरकार के तहत इस तरह के अतिक्रमण हटा दिए गए हैं और माफियाओं को उत्तर प्रदेश से बाहर

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-पनसीआर में पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि लंबे समय से यहां वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस अभय एस ओआ और उज्जल भुश्या की बेंच ने कहा कि सड़कों पर काम करने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रदूषण से प्रभावित होते हैं। हर किसी के पास अपने घर या कार्यस्थल पर वायु शुद्धिकरण यंत्र लगाने की सुविधा नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'पिछले छह महीनों में इस अदालत ने कई आदेश दिए हैं, जो दिखाते हैं कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति बहुत खराब रही है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वास्थ्य का अधिकार हर नागरिक का हक है, जिसमें स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि ग्रीन पटाखों से बेहद कम प्रदूषण होता है, तब तक इस बैन पर दोबारा विचार करने का सवाल ही नहीं उठता। दिल्ली में जो असाधारण स्थिति बनी हुई है, उसके चलते पटाखों पर रोक लगाना बिल्कुल जरूरी है।

पूर्व विधायक के नाती की हत्या फिरोजाबाद। थाना उत्तर क्षेत्र में दुकान बंद कर घर जा रहे भाजपा के पूर्व विधायक के नाती की कार से कुचल कर हत्या कर दी गई। मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामले में चार के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की है।कोटला मोहल्ला निवासी शिवम यादव (35) की रिंकी नाम की महिला के साथ कोटला रोड स्थित कपड़े की दुकान में साझेदारी थी। चर्चा है कि महिला का पति योगेंद्र से विवाद चल रहा था। योगेंद्र साथी भूरा, मुनीम और राजू के साथ कई बार दुकान पर आकर धमकी दे चुका है। मंगलवार रात चारों फिर से दुकान पर पहुंचे। यहां जमकर बहस होने लगी। इसके बाद जैसे ही शिवम दुकान के ताले लगाकर घर जाने लगा। सत्कार टाकीज कोटला रोड के सामने योगेंद्र ने साथियों के साथ मिलकर उसकी कार से टक्कर मार दी। इसमें शिवम गंभीर रूप से घायल हो गया और सड़क पर गिरकर कराने लगा। आरोपियों ने दोबारा शिवम के ऊपर कर चढ़ा दी, जिससे उसकी मौत हो गई।



विदेश सचिव जवानों की शहादत पर काट रहे केक

नेता प्रतिपक्ष बोले- चीन ने हमारी जमीन कब्जाई, पीएम चिट्ठियां लिख रहे

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को भारत-चीन के राजनयिक संबंधों की 75वीं सालगिरह के जश्न को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा- चीन हमारे 4 हजार वर्ग किमी इलाके पर कब्जा करके बैठा है, लेकिन मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि हमारे विदेश सचिव (विक्रम मिश्री) चीनी राजदूत के साथ केक काट रहे थे।

लोकसभा में शून्वका केल दौरान राहुल ने कहा, हम सामान्य स्थिति के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उससे पहले हमें अपनी जमीन वापस मिलनी चाहिए। मुझे पता चला कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने चीनी राजदूत को चिट्ठी लिखी है और यह भी हमें दूसरों से पता चल रहा है। चीनी राजदूत भारत के लोगों को बता रहे हैं कि उन्हें चिट्ठी लिखी गई। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने 1 अप्रैल को भारत-चीन संबंधों के



75 साल पूरे होने पर भारत में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। उन्होंने चीन के राजदूत फेइहोंग के साथ काटा था। फेइहोंग ने पर तस्वीरें शेयर की थीं। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने 1 अप्रैल को भारत-चीन संबंधों के 75 साल पूरे होने पर भारत में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। उन्होंने चीन के राजदूत शू फेइहोंग के साथ काटा था। फेइहोंग ने पर तस्वीरें शेयर की थीं। राहुल बोले- भाजपा की फिलॉस्फी हर विदेशी के सामने सिर झुकाना: मोदी सरकार की विदेश

नीति पर राहुल गांधी ने कहा, एक तरफ आपने चीन को हमारी जमीन दे दी और दूसरी तरफ अमेरिका ने हम पर टैरिफ (जैसे को तैसा टैक्स) लगा दिया। इससे देश की ऑटो, फार्मास्यूटिकल और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री तो पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। राहुल ने कहा, एक बार किसी ने इर्झरा जी से पूछा कि विदेश नीति के मामले में आप बाएं झुकती हैं या दाएं। इस पर उन्होंने जवाब दिया की मैं बाएं या दाएं नहीं झुकती। मैं भारतीय हूं और सीधी खड़ी हूं। भाजपा और परर की फिलॉस्फी अलग है। जब उनसे पूछा जाता है तो वे कहते हैं नरेश, नहीं, हम हर विदेशी के सामने अपना सिर झुकाते हैं। यह उनके इतिहास में है, हम जानते हैं। सरकार को जवाब देना चाहिए कि वह अमेरिकी टैरिफ पर क्या कर रही है। बीते दिन अमेरिका ने भारत पर 26 प्रतिशत जैसे को तैसा टैक्स

लगाने की घोषणा की है। अमेरिका ने कहा है कि भारत अमेरिकी सामानों पर बहुत ज्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी (आयात शुल्क) लगाता है। 2020 की गलवान झड़प में 20 भारतीय जवान हुए थे शहीद : लक्षाख की गलवान घाटी में 15 जून 2020 को भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई थी। 15 जून 2020 को चीन ने ईस्टर्न लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों में एक्सरसाइज के बहाने सैनिकों को जमा किया था। इसके बाद कई जगह पर घुसपैठ की घटनाएं हुई थीं। भारत सरकार ने भी इस इलाके में चीन के बराबर संख्या में सैनिक तैनात कर दिए थे। हालात इतने खराब हो गए कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर गोलीयां चलीं। इसी दौरान 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे।

सुप्रीम कोर्ट बोला, सिलेक्शन प्रॉसेस गलत

पश्चिम बंगाल में 25,753 शिक्षकों की बर्खास्तगी का आदेश रहेगा बरकरार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द कर नए सिरे से चयन प्रक्रिया 3 महीने में पूरा करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के स्कूल भर्ती घोटाले से जुड़े कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। पश्चिम बंगाल में एसएससी ने 2016 में 25 हजार शिक्षकों और गैर-शिक्षकों को नियुक्ति की थी। हाईकोर्ट ने इन नियुक्तियों को अवैध करार देते हुए कर्मचारियों को बर्खास्त किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की जांच को सही माना और कहा कि पूरी प्रक्रिया में धोखाधड़ी की गई। इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने सुनवाई की। शीर्ष कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिकाएं दायर की गई थीं। इसके साथ ही सीबीआई जांच के कलकता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर 4 अप्रैल को सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पश्चिम बंगाल भाजपा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 2016 में स्टेट लेवल



सिलेक्शन टेस्ट-2016 के जरिए सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती की थी। तब 24,640 रिक्त पदों के लिए 23 लाख से अधिक लोगों ने भर्ती परीक्षा दी थी। इस भर्ती में 5 से 15 लाख रुपए तक की घूस लेने का आरोप है। मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट को कई शिकायतें मिली थीं।

ममता बोलीं- निजी तौर पर फैसला स्वीकार नहीं : सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ देर बाद ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पैसे के बदले बेचा गया।

से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार नहीं करती हैं, लेकिन उनकी सरकार इसे लागू करेगी और चयन प्रक्रिया को फिर से दोहराएगी। उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या विपक्षी भाजपा और सीपीएम चाहते हैं कि बंगाल की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाए। उन्होंने कहा, इस देश के नागरिक के रूप में मेरे पास हर अधिकार है और मैं जजों के प्रति सम्मान के साथ इस फैसले को स्वीकार नहीं कर सकती। मैं मानवीय दृष्टिकोण से अपनी राय व्यक्त कर रही हूं। गलत सूचना न दें या भ्रम पैदा न करें। सरकार फैसले को स्वीकार करती है। स्कूल सेवा आयोग से भर्ती प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के लिए कहा है। भाजपा बोलीं- भ्रष्टाचार की पूरी जिम्मेदारी सीएम की : राज्य भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजुमदार ने एक्स पर पोस्ट कर कहा - 'शिक्षक भर्ती में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की पूरी जिम्मेदारी राज्य की विफल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ममता बनर्जी के शासन में कैसे पश्चिम बंगाल में शिक्षित बेरोजगार युवाओं की योग्यता को पैसे के बदले बेचा गया।

